LiFE Lifestyle For Environment

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

बीईई लाईन

अंक - 28, जुलाई - सितम्बर 2025

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

महानिदेशक महोदय का संदेश	01
सचिव बीईई महोदय का संदेश	02
ADEETIE योजना का आधिकारिक शुभारंभ: औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम	03
ADEETIE क्लस्टर-स्तरीय कार्यशाला - पश्चिम बंगाल	05
ऊर्जा दक्षता सहयोग के नए अवसरों की खोज	06
बीईई ने उर्जा दक्षता बढ़ाने में भूमिका निभाने वाले मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर्स का किया सम्मान	07
गांधीनगर में ECSBC कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित	08
तिरुवनंतपुरम में ECSBC पर दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित	09
सचिव, BEE, श्री मिलिंद देवरे ने FAN समिट एवं प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया	10
BEE ने 'Transforming India 2025' एक्सपो में ऊर्जा दक्षता पहलों का प्रदर्शन किया	11
कोल्हापुर में महाराष्ट्र के पहले एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन	13
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024: भारत के ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना	15
एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा: बेगूसराय, बिहार में ADEETIE कार्यशाला आयोजित	16
भारत का कार्बन बाज़ार: अनुच्छेद 6.2 के कार्यान्वयन पर बीईई की सक्रिय पहल	18
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया	19
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हिन्दी पखवाड़ा 2025 उत्साह और समर्पण के साथ मनाया	21
भारत के ऊर्जा संक्रमण और अनुकूलन एजेंडा के लिए जलवायु वित्त परिदृश्य का रूपांतरण	24

बीईई लाईन
अंक - 28, जुलाई - सितम्बर 2025 त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 28
जुलाई - सितम्बर 2025

संपादक मंडल
Editorial Board

बोर्ड के अध्यक्ष
महानिदेशक, बीईई
Chairman of the Board
DG, BEE

प्रधान संपादक
सचिव
Principal Editor
Secretary

संपादक
मीडिया प्रबंधक
Editor
Media Manager

अस्वीकरण: सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तिका की सामग्री के इस्तेमाल के सभी अधिकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के पास सुरक्षित हैं। इसमें शामिल सामग्री का कोई भी भाग प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलैक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Disclaimer: All rights reserved. All export rights for this book vest exclusively with the Bureau of Energy Efficiency (BEE). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievable system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher. Unauthorized use of the content is subject to legal action.

महानिदेशक
महोदय का संदेश

यह तिमाही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए उपलब्धि, सहभागिता और प्रेरणा में से एक रही है। पानीपत में एडीईईटीआईई (ADEETIE) योजना के सफल राष्ट्रीय शुभारंभ से लेकर कोल्हापुर में महाराष्ट्र के प्रथम ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना तक, ब्यूरो ने नीतियों को प्रभावी बनाने और ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरन्तर कार्रवाई की प्रतिबद्धता दिखाई है।

इस अंक में प्रस्तुत प्रत्येक पहल ब्यूरो की बढ़ती पहुँच को रेखांकित करती है—चाहे वह एमएसएमई क्षेत्र का रूपांतरण हो या सतत भवनों को सक्षम बनाना, मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा—परीक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान हो या कार्बन बाजार और जलवायु वित्त पर संवाद को आगे बढ़ाना। ये सभी प्रयास मिलकर एक ऊर्जा—दक्ष और निम्न—कार्बन भारत की नींव को सुदृढ़ कर रहे हैं।

"Transforming India 2025" प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का राष्ट्रीय मंचों पर हमारी भागीदारी तथा स्वच्छता पखवाड़ा और हिंदी पखवाड़ा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन न केवल ऊर्जा संरक्षण के प्रति बल्कि स्वच्छता, समावेशिता और भाषायी एकता जैसे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति भी ब्यूरो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सहयोग, नवाचार और जागरूकता के माध्यम से हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऊर्जा—सुरक्षित और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

सचिव
महोदय का संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बीईई लाइन के इस संस्करण के सभी पाठकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। पिछली तिमाही भारत की ऊर्जा दक्षता यात्रा में प्रगति और साझेदारी का उल्लेखनीय अवधि रही है। एडीईईटीआईई (ADEETIE) योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ हमारे सतत औद्योगिक विकास की सामूहिक खोज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को किफायती वित्तीय सहयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सशक्त बनाने पर केंद्रित यह योजना केवल औद्योगिक रूपांतरण ही नहीं, बल्कि समान और हरित विकास की एक दूरदर्शी पहल भी है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 जैसे प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया है, जो राज्यों के स्तर पर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु बढ़ती गति को दर्शाता है। गुजरात और केरल में आयोजित ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ECSBC) पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं ने हमारे इस संकल्प को और सुदृढ़ किया है कि भारत का बुनियादी ढाँचा ऊर्जा दक्ष एवं जलवायु अनुकूल बने।

जब हम 2070 तक राष्ट्रीय नेट जीरो लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो यह देखकर उत्साहवर्धन होता है कि उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज सभी मिलकर ऊर्जा दक्षता को विकास का प्रमुख आधार बनाने में योगदान दे रहे हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए ऐसी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है, जो जनसशक्तिकरण को प्रोत्साहित करें, नवाचार को बढ़ावा दें और प्रकृति के साथ सामंजस्य में सतत विकास को सुनिश्चित करें।

ADEETIE योजना का आधिकारिक शुभारंभ: औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम

पानीपत, हरियाणा : 15 जुलाई 2025 – भारत के हरित औद्योगिक परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में, विद्युत मंत्रालय ने "असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स (ADEETIE)" योजना का शुभारंभ किया।

यह राष्ट्रीय शुभारंभ आर्य (पी.जी.) कॉलेज, पानीपत, हरियाणा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय विद्युत एवं आवास तथा शहरी कार्य मंत्री, श्री मनोहर लाल ने की।

1000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ, ADEETIE योजना विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य MSMEs को उन्नत ऊर्जा–दक्ष प्रौद्योगिकियों और व्यवस्थाओं से सुसज्जित करना है, जिससे एक निम्न–कार्बन और उच्च–दक्षता वाला औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- वित्तीय सहायता: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5% और मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज सबवेंशन।
- तकनीकी सहयोग: इसमें निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs), प्रौद्योगिकी पहचान, और निगरानी एवं सत्यापन (M&V) शामिल हैं।
- लक्षित क्षेत्र एवं कवरेज: 14 ऊर्जा–गहन क्षेत्रों के 160 MSME क्लस्टरों को शामिल किया जाएगा। यह कार्य 2025–26 से 2027–28 के बीच चरणबद्ध तरीके से होगा।
- निवेश जुटाना: इस योजना का लक्ष्य 9000 करोड़ रुपये के स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश को उत्प्रेरित करना है, जिसमें से लगभग 6750 करोड़ रुपये MSME ऋण से अपेक्षित हैं।

माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री मनोहर लाल ने पानीपत में एडीईईटीआईई योजना का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय शुभारंभ की झलकियाँ

शुभारंभ कार्यक्रम में MSME उद्योग निकायों और प्रौद्योगिकी भागीदारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

- माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री मनोहर लाल ने योजना का उद्घाटन किया, आधिकारिक पोर्टल (adeetie.beeindia.gov.in) और पुस्तिका जारी की, और ADEETIE को MSMEs के लिए एक परिवर्तनकारी पहल बताया।
- श्री पंकज अग्रवाल, सचिव, विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता और वित्तीय पहुँच बढ़ाने के बीईई के प्रयासों की सराहना की।
- श्री ए.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), हरियाणा ने MSMEs को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने का आग्रह किया।
- श्री आकाश त्रिपाठी, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय एवं महानिदेशक, बीईई ने बताया कि यह योजना 9000 करोड़ रुपये के हरित निवेश को उत्प्रेरित करेगी।
- हरियाणा सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जैसे श्री कृष्ण लाल पंवार और श्रीमती प्रियंका सोनी ने भी MSMEs के इस परिवर्तनकारी कदम का पुरजोर समर्थन किया।

हरित भारत के लिए हरित विकास

ADEETIE योजना का शुभारंभ भारत की ऊर्जा दक्षता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह MSMEs को अपने संचालन में सुधार लाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करेगी। यह पहल भारत की राष्ट्रीय लक्ष्य (NDCs) और 2070 तक नेट–जीरो लक्ष्य के अनुरूप है। यह हरित विकास और सतत औद्योगिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है।

ADEETIE
पश्चिम बंगाल में क्लस्टर-स्तरीय कार्यशाला

कोलकाता, पश्चिम बंगाल : 4 जुलाई 2025 – "औद्योगिक एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की स्थापना हेतु सहायता (ADEETIE)" योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य नामित एजेंसी (WBSDA) ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एक दिवसीय क्लस्टर–स्तरीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य MSMEs में ऊर्जा–दक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और योजना के तहत उपलब्ध तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग पर प्रकाश डालना था।

कोलकाता में आयोजित एडीईईटीआईई क्लस्टर-स्तरीय कार्यशाला में एमएसएमई प्रतिनिधि एवं हितधारक।

उद्घाटन सत्र

WBSDA, Council for Leather Exports (CLE) और BEE के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा भारत की निम्न–कार्बन विकास यात्रा में ऊर्जा दक्षता की भूमिका पर बल दिया।

तकनीकी चर्चाएं

- श्री प्रदीप धिंगरा, निदेशक, PGSEPL ने ऊर्जा दक्षता के सर्वोत्तम अभ्यासों और डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी, विशेषकर MSME फाउंड्री क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित किया।

- डॉ. संजय चक्रवर्ती, प्रोफेसर, Government College of Engineering and Leather Technology ने चमड़ा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नई तकनीकें ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकती हैं।

हितधारकों की भागीदारी

इस कार्यशाला में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें हावड़ा और कोलकाता क्लस्टर के MSME मालिक, प्रौद्योगिकी प्रदाता और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया और अपने परिचालन को उन्नत करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु ADEETIE योजना का लाभ लेने में गहरी रुचि दिखाई।

MSME परिवर्तन की दिशा में अग्रसर

पश्चिम बंगाल में आयोजित यह कार्यशाला ADEETIE योजना को औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का उत्प्रेरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई। इसने MSMEs विशेषज्ञों और वित्तीय भागीदारों को एक साथ लाकर ऊर्जा दक्षता, स्थिरता और हरित विकास की ओर परिवर्तन को मजबूत किया।

ऊर्जा दक्षता सहयोग के नए अवसरों की खोज

दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल : 18 जुलाई 2025 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के दल ने CSIR–Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI) का दौरा किया ताकि ऊर्जा प्रबंधन और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के अवसर तलाशे जा सकें।

इस दौरे ने रचनात्मक संवाद का मंच प्रदान किया, जहाँ संभावित संयुक्त पहलों पर विचार किया गया। इनमें मुख्य रूप से शामिल थे:

- ऊर्जा दक्षता से संबंधित नवाचार
- प्रौद्योगिकियों की तैनाती और उनका विस्तार
- अनुसंधान–आधारित साझेदारी

यह संवाद भारत के ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए विज्ञान–नीति सहयोग की बढ़ती महत्ता को उजागर करता है। अनुसंधान विशेषज्ञता को नीति क्रियान्वयन के साथ जोड़कर यह साझेदारी सतत औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा–बचत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने में सहायक होगी।

बीईई और सीएमईआरआई दोनों ने अपनी संस्थागत क्षमताओं को मिलाकर बड़े पैमाने पर असरदार समाधान तैयार करने में गहरी रुचि व्यक्त की, जो सीधे तौर पर भारत के ऊर्जा संरक्षण और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देंगे।

ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त शोध हेतु सीएसआईआर-सीएमईआरआई के दौरे पर बीईई अधिकारी।

बीईई ने उर्जा दक्षता बढ़ाने में भूमिका निभाने वाले मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर्स का किया सम्मान

नई दिल्ली : 23 जुलाई, 2025 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने AITDC (UTPRERAK), NPTI, बदरपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत की ऊर्जा दक्षता आंदोलन में मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिटर्स (AEAs) के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया गया।

तकनीकी उत्कृष्टता की मान्यता

इस कार्यक्रम में AEAs के अथक प्रयासों से सम्बन्धित समारोह मनाया गया, जिन्होंने उद्योगों और संस्थाओं में प्रभावशाली ऊर्जा बचत उपाय लागू किए। अग्रिम पंक्ति के तकनीकी विशेषज्ञ और क्षेत्रीय प्रैक्टिशनर के रूप में, AEAs देशव्यापी ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

ज्ञान साझा करना और अंतर्दृष्टि

आधे दिन के इस कार्यक्रम में इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए गए, जहाँ AEAs ने:

- धरातलीय अनुभव और सफलता की कहानियाँ साझा की
- मापनीय ऊर्जा बचत दिखाने वाले केस स्टडी प्रस्तुत किए
- क्षेत्रीय चुनौतियों और नवाचारी समाधानों को उजागर किया

इन चर्चाओं ने औद्योगिक स्थिरता को बढ़ावा देने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को मजबूत करने के व्यावहारिक रणनीतियों में महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान की।

सततता के प्रति प्रतिबद्धता

BEE ने AEAs की समर्पण और विशेषज्ञता की बहुत सराहना की, और भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के मिशन में उनकी केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया। इस कार्यक्रम ने डोमेन विशेषज्ञों के साथ निरंतर जुड़ाव के महत्व को भी रेखांकित किया, ताकि एक ऊर्जा–प्रतिरोधी, कुशल और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार औद्योगिक परिदृश्य का निर्माण किया जा सके।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में योगदान हेतु बीईई द्वारा ऊर्जा परीक्षकों का सम्मान।

गांधीनगर में ECSBC कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित

गांधीनगर, गुजरात : 24–25 जुलाई, 2025 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) के सहयोग से पश्चिमी क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन कोड (ECSBC) के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की।

कार्यशाला का उद्देश्य

दो दिवसीय कार्यशाला ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया:

- पश्चिमी राज्यों में ECSBC कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना
- हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना
- सतत निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय क्रियाओं का समन्वय करना

सतत निर्माण के लिए दिशा निर्देश

भारत की ऊर्जा तीव्रता कम करने और हरित अवसंरचना का विस्तार करने की दिशा में प्रयासों के मद्देनजर, कार्यशाला में निर्माण क्षेत्र में जलवायु–संवेदनशील भवन प्रथाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका

BEE और GEDA दोनों ने भारत के ऊर्जा संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति और 2070 तक नेट जीरो की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। कार्यशाला ने राज्य–स्तरीय भागीदारी और समन्वित रणनीतियों की भूमिका को दोहराया, जो पश्चिमी क्षेत्र में सतत, ऊर्जा–कुशल और लचीले अवसंरचना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।

गांधीनगर में ईसीएसबीसी कार्यान्वयन पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यशाला के प्रतिभागी।

तिरुवनंतपुरम में ECSBC पर दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित

तिरुवनंतपुरम, केरल : 14–15 अगस्त, 2025 – ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन निर्माण (ECSBC) पर दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला ने नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और हितधारकों को सतत भवन प्रथाओं और ऊर्जा दक्षता उपायों पर विचार–विमर्श के लिए एकत्र किया।

आयोजन और सहयोग

इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने केरल के एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (EMC) के सहयोग से किया। यह कार्यशाला सतत निर्माण में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई।

उद्घाटन झलकियां

- कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन श्री के. कृष्णंकुट्टी, विद्युत मंत्री, केरल सरकार द्वारा किया गया, जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण में केरल के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने केरल एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड रूल्स, 2025 (KECSBCR) के नोटिफिकेशन को सतत निर्माण प्रथाओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बताया।
- श्री पुनीत कुमार, IAS, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पावर), केरल सरकार द्वारा एक विशेष वीडियो संदेश दिया गया, जिसमें प्रभावी कोड कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

कार्यशाला का फोकस

आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और दिल्ली के 60 से अधिक प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ, कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

- ECSBC कोड का कार्यान्वयन
- हरित निर्माण के लिए संसाधन जुटाना
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना

कार्यशाला ने ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया, जिससे भारत की ऊर्जा संरक्षण रूपरेखा में सतत भवन प्रथाओं को शामिल करने के सामूहिक मिशन को मजबूती मिली। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहयोग को बढ़ावा देकर, इस कार्यक्रम ने भारत के ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों और नेट जीरो प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय गति को मजबूत किया।

केरल में ईसीएसबीसी दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन सत्र।

सचिव, BEE, श्री मिलिंद देवरे ने FAN समिट एवं प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश : 21–23 अगस्त, 2025 – FAN समिट एवं प्रदर्शनी 2025, अपने तरह की पहली पहल, इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम ने भारत के महत्वपूर्ण पंखा उद्योग के भविष्य को आकार देने में नवाचार और ऊर्जा दक्षता की परिवर्तनकारी भूमिका को प्रदर्शित किया।

उद्घाटन समारोह

कार्यक्रम का उदघाटन श्री मिलिंद देवरे, सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया गया, जिन्होंने भारत की ऊर्जा दक्षता यात्रा में सतत शीतलन समाधान और उद्योग परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया।

प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण

तीन दिनों के दौरान इस कार्यक्रम में भारत भर के 120 प्रदर्शकों और उद्योग हितधारकों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रदर्शनी में निम्नलिखित प्रस्तुत किए गएरू

- पूर्ण पंखा इकोसिस्टम – पारंपरिक छत और एग्जॉस्ट फैंस से लेकर BLDC मोटर्स, स्मार्ट कंट्रोलर्स और डिजाइनर मॉडल तक
- प्रौद्योगिकी साझेदार – डाई–कास्टिंग विशेषज्ञ, सेमीकंडक्टर प्रदाता और स्मार्ट कूलिंग उत्पादों में नवप्रवर्तनकर्ता
- इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म– निर्माता, नवप्रवर्तनकर्ता, नीति निर्माता और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच संवाद की सुविधा

सतत शीतलन समाधान को बढ़ावा देना

FAN समिट एवं प्रदर्शनी 2025 ने भारत के शीतलन और पंखा उद्योग में ऊर्जा–कुशल तकनीकों के बढ़ते महत्व को उजागर किया, जो रोजमर्रा की सुविधा और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उद्योग–व्यापी सहयोग को बढ़ावा देकर, समिट ने स्मार्ट और हरित शीतलन समाधान की दिशा में तकनीक, नीति और बाजार भागीदारी की भूमिका को मजबूत किया।

इस कार्यक्रम ने यह भी रेखांकित किया कि इस स्तर के उद्योग मंच भारत के विकासात्मक दृष्टिकोण "विकसित भारत 2047" और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता में कैसे योगदान देते हैं।

बीईई सचिव श्री मिलिंद देवरे ने फैन समिट एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

BEE ने 'Transforming India 2025' एक्सपो में ऊर्जा दक्षता पहलों का प्रदर्शन किया

नई दिल्ली : 24–26 अगस्त, 2025 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में तीन दिवसीय "Transforming India 2025" एक्सपो में भाग लिया, जिसमें भारत के ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर किया गया। BEE का स्टॉल प्रमुख योजनाओं, नवाचारपूर्ण कार्यक्रमों और सतत प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक सक्रिय मंच के रूप में कार्य करता रहा, जो देश की "विकसित भारत 2047" और "नेट जीरो 2070" की यात्रा को आकार दे रहे हैं।

पहला दिनः BEE स्टॉल पर गणमान्य अतिथि

उद्घाटन दिवस पर सार्वजनिक भागीदारी उत्साही रही, जिसमें आगंतुकों ने BEE की पहलों में गहरी रुचि दिखाई। इस दिन को विशेष बनाने वाले दो प्रमुख अतिथि थेः

- श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, माननीय राज्यपाल, त्रिपुरा, ने स्टॉल का दौरा किया, BEE के क्रॉस–सेक्टोरल कार्यक्रमों की सराहना की और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की प्रशंसा की।
- आचार्य बालकृष्ण, प्रबंध निदेशक, पतंजलि आयुर्वेद, ने भी स्टॉल का दौरा किया और नागरिकों को ऊर्जा–जागरूक और सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इन यात्राओं ने BEE टीम को और अधिक प्रेरित किया और इसकी आउटरीच पहलों के प्रभाव को बढ़ाया।

दूसरा दिनः गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को जोड़ना

एक्सपो के दूसरे दिन भी उच्च स्तर की भागीदारी रही, जिसका फोकस निम्नलिखित विषयों पर थाः

- सतत भवन प्रथाएं
- ऊर्जा–कुशल उपकरण
- औद्योगिक दक्षता और डिमांड–साइड प्रबंधन

ऊर्जा संरक्षण क्विज और ऊर्जा शपथ जैसी इंटरएक्टिव गतिविधियों ने विशेष रूप से छात्रों और युवा पेशेवरों की अच्छी भागीदारी सुनिश्चित की। ये मनोरंजक और शैक्षिक गतिविधियाँ जागरूकता को गहरा करती हैं और ऊर्जा बचाने के लिए सरल जीवनशैली परिवर्तन को प्रेरित करती हैं।

तीसरा दिनः हरित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास

अंतिम दिन, 26 अगस्त, पर और भी बड़ी सार्वजनिक भागीदारी रही। विभिन्न पृष्ठभूमि के नागरिकों ने स्टॉल का दौरा किया और संवाद किया और बड़ी संख्या में ऊर्जा संरक्षण की शपथ में शामिल हुए। यह जीवंत वातावरण ऊर्जा दक्षता के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय जागरूकता और हरित भारत निर्माण में सामूहिक प्रयास के महत्व को दर्शाता है।

मुख्य निष्कर्ष

"Transforming India 2025" एक्सपो में BEE की भागीदारी ने निम्नलिखित अवसर प्रदान किएः

- विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पहलों का प्रदर्शन
- नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं और जनता से जुड़ना
- नागरिकों को ऊर्जा–कुशल प्रथाएं अपनाने के लिए प्रेरित करना

उत्साही प्रतिक्रिया, गणमान्य अतिथियों की सराहना और सक्रिय नागरिक भागीदारी ने भारत के ऊर्जा–सुरक्षित भविष्य के लिए नवाचार, जागरूकता और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने में BEE की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया।

सतत ऊर्जा समाधान पर प्रदर्शनी में बीईई स्टॉल पर जानकारी प्राप्त करते आगंतुक।

कोल्हापुर में महाराष्ट्र के पहले एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन

कोल्हापुर : 22 अगस्त, 2025 – महाराष्ट्र ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जब कोल्हापुर फाउंड्री एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में राज्य के पहले एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन श्री मिलिंद देवरे, सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया गया, जो भारत की कम–कार्बन और ऊर्जा–सुरक्षित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए एक हब

एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को उद्योगों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है:

- ऊर्जा दक्षता अवसरों की पहचान के लिए उन्नत ऊर्जा ऑडिट
- औद्योगिक पेशेवरों के कौशल बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- डिजिटल समाधान, जो विभिन्न क्षेत्रों में 15–20% ऊर्जा बचत सक्षम बनाते हैं

लक्षित उद्योगों में फाउंड्री, इंजीनियरिंग, चीनी, वस्त्र और स्वास्थ्य देखभाल शामिल हैं, जिससे यह केंद्र नवाचार और ज्ञान साझा करने का एक बहु–क्षेत्रीय हब बनता है।

ADEETIE के माध्यम से MSME संक्रमण को बढ़ावा

केंद्र का एक प्रमुख फोकस उद्योगों को ऊर्जा–कुशल तकनीकों को अपनाने में सहायता करना है, जो "Assistance in Deploying of Energy Efficient Technologies in Industries and Establishments (ADEETIE)" योजना के तहत किया जाएगा।

- MSMEs को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्राप्त होगी
- इससे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना आसान होगा
- निरन्तरता की दिशा में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित किया जाएगा

श्री मिलिंद देवरे ने महाराष्ट्र के प्रथम ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, कोल्हापुर का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय मिशनों के साथ पंक्तिबद्ध

यह पहल औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और भारत के राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोण दोनों को मजबूत करती है:

- नवाचार–आधारित विकास के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 का समर्थन
- भारत के नेट जीरो 2070 मिशन में योगदान
- दिखाती है कि कैसे ऊर्जा दक्षता और डिकार्बोनाइजेशन आर्थिक प्रगति के साथ हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं

आगे की दिशा

कोल्हापुर एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनने के लिए तैयार है, और भारत भर में इसकी प्रतिकृति प्रेरित करेगा। सहयोग को बढ़ावा देकर, उद्योगों को सशक्त बनाकर और स्वच्छ तकनीकों को प्रोत्साहित करके, यह सतत और लचीले औद्योगिक विकास की दिशा में बदलाव को तेज करेगा।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024: भारत के ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना

नई दिल्ली : 26 अगस्त, 2025 – विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और एलायंस फॉर एनर्जी एफिशियंट इकॉनमी (AEEE) के सहयोग से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 जारी किया। छठवें संस्करण में प्रवेश कर चुका यह सूचकांक FY 2023–24 के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

SEEI 2024 की रूपरेखा

SEEI 2024 सात प्रमुख क्षेत्रों में 66 सूचकों पर आधारित है – भवन, उद्योग, परिवहन, कृषि, नगरपालिका सेवाएँ, डिस्कॉम्स और क्रॉस–सेक्टर पहल। यह दर्शाता है कि राज्य राष्ट्रीय ऊर्जा प्राथमिकताओं को मापनीय कार्यों में कैसे बदल रहे हैं। लॉन्च के समय, श्री आकाश त्रिपाठी, महानिदेशक, BEE ने उल्लेख किया:

ऊर्जा दक्षता 2070 तक नेट जीरो की दिशा में भारत की यात्रा और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी हासिल करने की आधारशिला है।

SEEI 2024 की मुख्य विशेषताएँ

- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने अपने–अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- फ्रंट रनर्स: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु ने अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखी।

क्षेत्रीय प्रगति:

- भवन: 24 राज्यों ने ECBC 2017 अधिसूचित किया
- MSME: 10 राज्यों ने समर्पित ऊर्जा दक्षता नीतियाँ अपनाई
- जलवायु कार्रवाई: 25 राज्यों ने क्लाइमेट/हीट एक्शन प्लान विकसित किए
- परिवहन: 31 राज्यों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीतियाँ लागू की
- कृषि: केरल ने सौर या ऊर्जा–कुशल पंपों को 74% अपनाया

राज्य–स्तरीय कार्रवाई को मजबूत करना

2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना (SEEAPs) तैयार किए, जिनमें से 31 ने कार्यान्वयन को तेज करने के लिए राज्य–स्तरीय संचालन समितियाँ बनाई।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, नीति मार्गदर्शन प्रदान करके और ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके, SEEI भारत के ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है।

नई दिल्ली में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 का अनावरण करते गणमान्यजन।

एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा: बेगूसराय, बिहार में ADEETIE कार्यशाला आयोजित

बेगूसराय, बिहार : 1 सितम्बर 2025 — ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, ने उद्योगों और संस्थाओं में ऊर्जा दक्ष तकनीकों की स्थापना में सहायता (ADEETIE) योजना के तहत एक दिवसीय क्लस्टर–स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना था।

एमएसएमई को ऊर्जा दक्षता के लिए सशक्त बनाना

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उद्योग हितधारकों, विशेष रूप से ईंट निर्माण इकाइयों, को ऊर्जा दक्ष तकनीकों के लाभ और ADEETIE योजना के तहत उपलब्ध आर्थिक एवं तकनीकी सहायता के बारे में जागरूक करना था।

कार्यक्रम में श्री साकेत कुमार सिन्हा, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय श्री अजय यादव, प्रशिक्षु IAS; सुश्री ज्ञानेश्वरी किरण, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (DIC), बेगूसराय सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सरकारी और संस्थागत समर्थन

बैंक अधिकारियों ने विभिन्न वित्तीय योजनाओं और ऋण तंत्रों की जानकारी साझा की, जो MSMEs को साफ–सुथरी और अधिक दक्ष उत्पादन प्रणालियों की ओर संक्रमण करने में मदद करती हैं।

श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, और डॉ. कार्तिक अग्रवाल, उप सचिव, विद्युत मंत्रालय ने वर्चुअल रूप से संबोधन करते हुए प्रतिभागियों से ADEETIE योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊर्जा दक्षता न केवल उत्पादन लागत कम करती है, बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है और भारत के हरित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण का समर्थन करती है।

बेगूसराय में आयोजित एडीईईटीआईई कार्यशाला में भाग लेते एमएसएमई प्रतिनिधि।

सक्रिय भागीदारी और ज्ञान साझा करना

इस कार्यशाला में 150 से अधिक ईंट निर्माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने आधुनिक भट्टी तकनीक, ऊर्जा दक्ष प्रथाएं और ईंधन बचत तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो संचालन लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सहायक हैं। साथ ही ADEETIE और अन्य संबंधित सरकारी पहलों के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता तंत्र पर सत्र भी आयोजित किए गए।

हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता

कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा ADEETIE कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभिव्यक्ति (EoIs) प्रस्तुत करने के साथ हुआ, जिससे MSMEs में सतत औद्योगिक प्रथाओं को अपनाने की मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई दी।

इस कार्यशाला के माध्यम से, BEE और BREDA ने बिहार के MSME क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और भारत के निम्न–कार्बन भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप सतत और समावेशी औद्योगिक विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारत का कार्बन बाज़ार: अनुच्छेद 6.2 के कार्यान्वयन पर बीईई की सक्रिय पहल

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने यू.एस.–इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) द्वारा आयोजित उच्च–स्तरीय उद्योग संवाद में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस संवाद का उद्देश्य भारत के कार्बन बाजार में हाल के विकास तथा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करना था।

इस सत्र की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की संयुक्त सचिव श्रीमती नमिता प्रसाद ने की। उन्होंने कार्बन बाजार प्रशासन के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) की स्थापना और उसके कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बीईई की ओर से निदेशक श्री सौरभ डिड्डी ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इसे भारत की निम्न–कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण तथा जलवायु कार्रवाई के लिए बाजार–आधारित तंत्र को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

इस संवाद में उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, प्रोफेशनल सेवा कंपनियों, विधि विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों ने भाग लिया। चर्चाओं का केंद्र एनडीए, के संचालन ढांचे, हाल के नियामकीय विकास, प्रभावी ऑफसेट पद्धतियों तथा अनुपालन तंत्र की रूपरेखा पर रहा। इन विचार–विमर्शों ने पारदर्शी और प्रभावी कार्बन बाजार के निर्माण में बीईई की सक्रिय भूमिका को और मजबूती प्रदान की।

सत्र ने यह संदेश दिया कि वैश्विक स्तर पर संरेखित, विश्वसनीय और लचीले कार्बन बाजार पारितंत्र के लिए सरकारी एजेंसियों और उद्योग जगत के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है। बीईई ने यूएसआईबीसी तथा उद्योग सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और ऊर्जा दक्षता एवं कार्बन बाजार से संबंधित नवीन पहलों के माध्यम से भारत के जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया।

कार्बन बाज़ार और अनुच्छेद 6.2 पर विचार-विमर्श करते विशेषज्ञ एवं उद्योग नेतृत्वकर्ता।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया

17 सितम्बर – 2 अक्टूबर 2025 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने गर्व के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया, यह प्रतिबद्धता दोहराते हुए कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत विकास हमारी प्राथमिकताएँ हैं। यह आयोजन का मार्गदर्शी सिद्धांत है।

"स्वच्छता से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से समृद्धि, और समृद्धि से विकास होता है।"

इस अवसर ने सामूहिक जिम्मेदारी की शक्ति को उजागर किया, जो एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक है।

स्वच्छता शपथ समारोह

BEE मुख्यालय में आयोजित स्वच्छता शपथ समारोह के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थलों, आसपास के क्षेत्रों और समुदायों में स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। इस समारोह ने यह स्पष्ट किया कि स्वच्छता केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि में योगदान देता है।

मुख्यालय में स्वच्छता शपथ लेते बीईई अधिकारी एवं कर्मचारी।

निबंध लेखन प्रतियोगिता: स्वच्छता के लिए युवाओं की आवाज

विचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, BEE ने स्वच्छता और सततता पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतिभागियों ने स्वच्छ भारत मिशन को हासिल करने में युवाओं की भूमिका का विश्लेषण किया और यह दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास सतत और दीर्घकालिक बदलाव ला सकते हैं।

वृक्षारोपण अभियान: हरित भविष्य का पोषण

BEE के अधिकारी और कर्मचारी #स्वच्छता_पखवाड़ा_2025 और #एक_पेड़_माँ_के_नाम अभियानों के तहत वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। इस प्रतीकात्मक पहल ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध को उजागर किया और सभी को हरित और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान।

वॉकाथॉनः जागरूकता फैलाना कदम दर कदम

उत्सव को एक सक्रिय रूप देने के लिए वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण और सतत जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और नागरिकों को छोटे लेकिन प्रभावशाली आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

स्वच्छता और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने हेतु बीईई कर्मचारियों द्वारा वॉकथॉन।

स्वच्छता अभियानः उदाहरण पेश करना

"स्वच्छता ही सेवा" के संदेश को मजबूत करने के लिए, BEE ने अपने कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई की, टीमवर्क, समर्पण और नागरिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। इस पहल ने यह दर्शाया कि स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना संगठनात्मक अनुशासन और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है।

बीईई परिसर के अंदर और आसपास स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया।

एक स्वच्छ और हरित भारत की ओर कदम

इन गतिविधियों के माध्यम से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्वच्छता, सततता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के सुरक्षा प्रहरी के रूप में आगे बढ़ता रहा, जो स्वच्छ भारत मिशन और भारत के सतत विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

आइए इस आंदोलन में शामिल हों! आइए हम सभी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ, हरित भारत के निर्माण में योगदान दें। इस सम्बन्ध मे हर छोटा कदम मायने रखता है!

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हिन्दी पखवाड़ा 2025 उत्साह और समर्पण के साथ मनाया

17 – 30 सितम्बर 2025

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने हिन्दी पखवाड़ा 2025 बड़े उत्साह के साथ मनाया, यह प्रतिबद्धता दोहराते हुए कि शासकीय पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे राष्ट्र की एकता की भाषा के रूप में मजबूत करना आवश्यक है। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे भाषाई गर्व और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन हो सके।

हिन्दी पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन

उत्सव का आरंभ सभी कर्मचारियों को हिंदी के प्रचार और सम्मान में सक्रिय योगदान देने के आह्वान के साथ हुआ। अधिकारियों ने यह रेखांकित किया कि हिंदी को सशक्त बनाना एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अंग्रेजी–हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता

द्विभाषी कौशल को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी–हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उनके अनुवाद कौशल में सुधार हुआ और प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रभावी उपयोग बढ़ा।

अंग्रेज़ी-हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता में भाग लेते कर्मचारी।

हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

17 सितम्बर को आयोजित हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में BEE की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग लिए। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की सृजनात्मक लेखन क्षमता का प्रदर्शन हुआ और यह स्पष्ट हुआ कि हिंदी अधिकारिक संचार का प्रभावी और सटीक माध्यम हो सकती है।

राजभाषा प्रश्न मंच प्रतियोगिता

22 सितम्बर को BEE ने राजभाषा प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिकारिक कार्यों में हिंदी के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना था। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विजेताओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान राजभाषा प्रश्न मंच प्रतियोगिता।

हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता

हिंदी पखवाड़ा की एक प्रमुख गतिविधि थी हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता, जिसमें BEE के अधिकारी एवं कर्मचारी ने बड़ी तत्परता और उत्साह के साथ भाग लिया। इस प्रतियोगिता ने अधिकारियों और कर्मचारियों के हिंदी के प्रचार में समर्पण और प्रतिबद्धता को उजागर किया।

विद्युत मंत्रालय एवं बीईई कर्मचारियों की भागीदारी के साथ हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता।

हिंदी पखवाड़ा के विजेताओं को पुरस्कार वितरण

30 सितम्बर 2025 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीईई के महानिदेशक श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए और उनके उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणादायी संदेश भी दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे आयोजन सफल और सार्थक बना।

हिंदी पखवाड़ा विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह।

भाषाई गर्व और राष्ट्रीय एकता का संदेश

इन सभी गतिविधियों के माध्यम से BEE ने यह दोहराया कि हिंदी न केवल शासकीय कार्यों को अधिक प्रभावी और सुगम बनाती है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गर्व और पहचान का प्रतीक भी है।

आइए हम सभी यह संकल्प लें कि सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिकतम उपयोग करेंगे, ताकि ऊर्जा संरक्षण का संदेश पूरे देश में एक ऐसी भाषा में पहुँचे जो हम सभी को जोड़ती हो।

भारत के ऊर्जा संक्रमण और अनुकूलन एजेंडा के लिए जलवायु वित्त परिदृश्य का रूपांतरण

भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह कम–कार्बन और जलवायु–लचीले विकास के मार्ग की ओर अग्रसर है। एक ओर बढ़ते उत्सर्जन और दूसरी ओर जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता के कारण, भारत की प्रगति पर्याप्त, पूर्वानुमेय और न्यायसंगत जलवायु वित्त प्रवाह पर निर्भर करती है। भारत ने लगातार UNFCCC प्लेटफार्मों, विशेषकर COP29 पर, दोहराया है कि जलवायु वित्त कोई बाजार अवसर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दायित्व है, जो समान किंतु भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR&RC) के सिद्धांत पर आधारित है। विकसित देशों को 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान और रियायती वित्त के रूप में जुटाने होंगे ताकि वैश्विक दक्षिण में शमन, अनुकूलन और ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन मिल सके।

भारत का ऊर्जा संक्रमण

भारत विश्व के सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तनों को क्रियान्वित कर रहा है, जो इसके पंचामृत लक्ष्यों और राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) पर आधारित है। इन लक्ष्यों में 2030 तक 50 प्रतिशत गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता और 2070 तक नेट–जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है। यद्यपि भारत ने कई लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त किया है, परंतु वित्तीय चुनौती अभी भी गंभीर है। अनुमान बताते हैं कि भारत को 2030 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2070 तक 19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा निवेश केवल 13 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष है–जो आवश्यक 68 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष से काफी कम है।

इस अंतर को समाप्त करने के लिए भारत ने कई सुधार किए हैं, जैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना, 2025 तक राष्ट्रीय जलवायु वित्त वर्गीकरण प्रणाली (taxonomy) विकसित करना, और जलवायु जोखिम प्रकटीकरण ढाँचा बनाना। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और हरित क्षेत्रों में जोखिम कम करने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन हैं।

जलवायु वित्त और न्याय

भारत की जलवायु वित्त संरचना केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ी है। न्यायपूर्ण संक्रमण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया श्रमिकों और कार्बन–निर्भर समुदायों के हितों की रक्षा करे। वैश्विक मंचों पर वादों के बावजूद अनुकूलन (Adaptation) वित्त, शमन (Mitigation) की तुलना में काफी कम है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि अनुकूलन वित्त को गरीबों पर केंद्रित, क्षेत्र–विशिष्ट और लक्षित बनाया जाए–जैसे जलवायु–सहिष्णु बुनियादी ढाँचा, स्मार्ट कृषि और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ।

शहरी लचीलेपन की अनिवार्यता

भारत के शहर, जो विकास के इंजन भी हैं और जलवायु जोखिम के केंद्र भी, लचीलेपन में भारी निवेश की माँग करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 2050 तक जलवायु–सहिष्णु शहरी बुनियादी ढाँचे पर 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आवश्यक होगा–जिसमें हरित भवन, ऊर्जा–कुशल जल प्रणाली और सतत परिवहन शामिल हैं। क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के अनुसार, 2030 तक हरित और सतत ऋण के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग होगी। अतः वित्त को लचीलापन निर्माण और प्रकृति–आधारित समाधानों की ओर पुनर्निर्देशित करना होगा।

वित्त से आगे–परिवर्तन की दिशा में

भारत की जलवायु वित्त रणनीति बहुआयामी और समानतापूर्ण है, जो घरेलू सुधारों, वैश्विक साझेदारी और मिश्रित वित्त (Blended Finance) मॉडलों पर आधारित है, ताकि सार्वजनिक और निजी पूंजी को बड़े पैमाने पर जुटाया जा सके। किंतु केवल वित्त से जलवायु संकट का समाधान नहीं होगा–यह सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। भारत का दृष्टिकोण जलवायु महत्वाकांक्षा और जलवायु न्याय को एक साथ जोड़ता है, जिससे वित्तीय प्रवाह लोगों, पारिस्थितिक तंत्रों और समावेशी विकास की सेवा में आएं। सही नीतियों और साझेदारियों के साथ भारत ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सकता है जहाँ ऊर्जा दक्षता और समानता मिलकर एक सतत और लचीले भविष्य की नींव बनें।